भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

भारत सरकार के मंत्रालय/विभागों में हिन्दी भाषा का सामान्य उपयोग बढ़ाने के लिए सरलीकरण एवं सुगम बनाए जाने हेतु वाक्यांश।

S.No.	Word in English	Meaning in Hindi	Usages in English	Usages in Hindi
1.	Apex Body	सर्वोच्च निकाय	The Ministry of Women & Child Development is the apex body of Government of India for formulation and administration of regulations and laws related to women & child development.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिलाओं और बच्चों के विकास से संबंधित नियमों और कानूनों को बनाने और उनका प्रवर्तन करने के लिए भारत सरकार का सर्वोच्च निकाय है।
2.	Gender Equality	महिला-पुरुष समानता	The Principle of gender equality is enshrined in the India Constitution.	महिला-पुरुष समानता का सिद्धांत भारत के संविधान में दिया गया है।
3.	Planning Process	योजना प्रक्रिया	Women secured a special place in the national plans & planning process primarily with thrusts on health, education & employment.	महिलाओं का राष्ट्रीय योजनाओं और योजना प्रक्रिया में विशेष स्थान सुरक्षित है जिसमें मुख्य रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर बल दिया गया है।
4.	Organized or unorganized	संगठित अथवा असंगठित	The sexual harassment at workplace (prevention, Prohibition & Redressed) Act, 2013 covers all women, irrespective of their age on employment status and protect their against sexual harassment at all work places whether organized or unorganized.	कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन-उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और शिकायत निपटान) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सभी महिलाएं आती हैं चाहे उनकी आयु अथवा रोजगार का दर्जा कुछ भी हो, चाहे संगठित अथवा असंगठित क्षेत्र के कार्यस्थल हो, महिलाओं के उत्पीड़न के विरुद्ध उनकी सुरक्षा करता है।
5.	Prohibition of child marriage	बाल विवाह का प्रतिषेध	The prohibition of child marriage Act, 2006 punishes those who promote, perform & abet child marriage.	बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अंतर्गत ऐसे लोगों को दंडित किया जाता है, जो बाल विवाह को बढ़ावा देते हैं, बाल विवाह कराते हैं और उसके लिए उकसाते हैं।
6.	Prevention of child marriage	बाल विवाह की रोकथाम	The Prevention of child marriage and protection of girl child is a prominent part of the National part of Action for Children, 2016.	बाल विवाह की रोकथाम और बालिकाओं का संरक्षण राष्ट्रीय बाल कार्य योजना, 2016 का एक प्रमुख भाग है।
7.	Trafficking	अवैध व्यापार	In order to address various aspects of trafficking-prevention, prosecution, protection of victims and witnesses and rehabilitation of victims-the ministry has conceptualized a comprehensive bill on trafficking.	अवैध व्यापार के विभिन्न पहलुओं/ समस्याओं निवारण, मुकदमा चलाने, पीड़ित लोगों और साक्ष्यों को संरक्षण प्रदान करने और पीड़ित व्यक्तियों का पुनर्वास करने के समाधान के लिए मंत्रालय ने अवैध व्यापार पर एक व्यापक विधेयक की परिकल्पना की है।
8.	Protection of women	महिलाओं की सुरक्षा	The Ministry is working to ensure protection of women both inside & outside the home.	मंत्रालय घर के भीतर और घर से बाहर दोनों स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य कर रहा है।
9.	Domestic Violence	घरेलू हिंसा	The implementation of the protection of women from Domestic Violence Act (PWDVA), 2005 is being pushed across the country.	घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण विधेयक, 2005 को पूरे देश में क्रियान्वित किया जा रहा है।
10.	Indecent	अशिष्ट रूपण	The Indecent Representation of Women Act,	स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम, 1986 को

	Representation		1986 was enacted with the specific objective of prohibiting the indecent representation of women.	स्त्री के अशिष्ट रूप को रोकने के विशिष्ट उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था।
11.	woman Help line	महिला हैल्पलाईन	To provide women with a 24X7 service, woman Help lines with uniform code 181 have been set up across the country.	महिलाओं को सातों दिनों 24 घंटे सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरे देश में एक समान 181 कोड वाली महिला हैल्पलाईनें बनाई गई हैं।
12.	Mahila Police Volunteers	महिला पुलिस वालेंटियर	The Ministry, in collaboration with MHA has recently started the engagement of Mahila Police Volunteers (MPVs) in States/UTs.	मंत्रालय ने हाल ही में गृह मंत्रालय के सहयोग से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महिला पुलिस वालेंटियर लगाना शुरू किया है।
13.	victims of unfortunate circumstances	दुखद परिस्थितियों की शिकार	The Swadhar Greh scheme targets women victims of unfortunate circumstances who are in need of institutional support for rehabilitation so that they could lead their life with dignity.	स्वाधार गृह स्कीम का लक्षित वर्ग दुखद परिस्थितियों की शिकार ऐसी महिलाएं है, ताकि वे सम्मान के साथ जीवन यापन कर सकें।
14.	Support to Training and Employment Programme	प्रशिक्षण और रोजगार हेतु सहायता	The Ministry had been administering 'Support to Training and Employment Programme (STEP) for Women'since 1986-87 as a Çemtral Sector Scheme'.	मंत्रालय केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम के रूप में 1986-87 से महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार हेतु सहायता (स्टेप) कार्यक्रम चला रहा है।
15.	Eligible organization	पात्र संगठन	Under the Ujjawala Scheme, assistance is provided to eligible organizations for undertaking above activities.	उज्ज्वला स्कीम के तहत उपर्युक्त गतिविधियों के लिए पात्र संगठनों को सहायता दी जाती है।
16.	Nirbhaya Fund	निर्भया कोष	Government of India set up a dedicated fund called "Nirbhaya Fund"in 2013, for implementation of initiatives aimed at enhancing the safety and security for women in the country.	देश में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई पहलों के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार ने 2013 में 'निर्भया कोष' नामक एक पृथक कोष की स्थापना की।
17.	Projects	परियोजनाएं	A number of projects are being implemented under the Nirbhaya Fund, which is managed by the Ministry for the safety and security of women.	महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस मंत्रालय द्वारा संचालित निर्भया कोष के अंतर्गत अनेक परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।
18.	Grievance Redressal Cell	शिकायत निवारण कक्ष	The Grievance Redressal Cell of the Ministry deals with the online grievances that are received on issues related to women and children.	मंत्रालय का शिकायत निवारण कक्ष महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुद्दों पर ऑनलाइन शिकायतों का निपटान करता है।
19.	Action Taken Reports	की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्टें	Action Taken Reports are prepared on weekly /monthly basis and are monitored regularly by the senior authorities.	साप्ताहिक/मासिक आधार पर की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्टें तैयार की जाती हैं और वरिष्ठ प्राधिकारियों द्वारा उनका नियमित रूप से अनुवीक्षण किया जाता है।
20.	International Women's Day	अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस	Ministry of Women & Child Development celebrates International Women's Day on 8th March every year.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हर वर्ष 08 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाता है।
21.	Census	जनगणना	Children in the age group 0-6 years constitute around 158 million of the population of india (2011 Census).	भारत की जनसंख्या में 0-6 वर्ष के बच्चों की संख्या लगभग 158 मिलियन है (जनगणना 2011)।
22.	Welfare, development and protection of children.	बच्चों का कल्याण, विकास और संरक्षण	The Ministry of Women and Child Development is administering various schemes for the welfare, development and protection of children.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बच्चों के कल्याण, विकास और संरक्षण के लिए कई स्कीमें चला रहा है।
23.	Flagship programme	प्रमुख कार्यक्रम	The Anganwadi Services Scheme is one of the flagship programmes of the Government of India and represents one os the world's largest and unique programmes for early	समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्कीम भारत सकरार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है और यह

			childhood care and development.	प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल तथा विकास के लिए चलाए जाने वाले विश्व के सबसे बड़े और अद्वितीय कार्यक्रमों में से एक है।
24.	Key feature	प्रमुख विशेषता	For better governance in the delivery of the Scheme, convergence is therefore, one of the key features of the Anganwadi Services Scheme.	स्कीम में सेवाओं की प्रदायगी के बेहतर नियंत्रण के लिए, अभिसरण आईसीडीएस स्कीम की एक प्रमुख विशेषता है।
25.	Pregnant women and lactating mothers	गर्भवती महिलाएं एवं धात्री माताएं	All children below 6 years of age, pregnant women and lactating mothers are eligible for availing of services under the Anganwadi Services Scheme.	छह वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों तथा गर्भवती महिलाएं एवं धात्री माताएं आंगनवाड़ी केंद्रों पर आईसीडीएस के अंतर्गत दी जाने वाली सेवाओं को पाने के पात्र हैं।
26.	Add-on scholarship	अतिरिक्त छात्रवृत्ति	A free add-on scholarship benefit is available for the children of Anganwadi Workers covered under the AKBY Scheme.	एकेबीवाई स्कीम में बीमित आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के बच्चों को नि:शुल्क अतिरिक्त छात्रवृत्ति लाभ उपलब्ध है।
27.	Anganwadi Worker	आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री	The Government of India first formulated a scheme of award for Anganwadi Workers at the National Level and State Level for the year 2000-2001.	भारत सरकार ने पहले वर्ष 2000-2001 में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर पुरस्कार की स्कीम तैयार की थी।
28.	Active area	क्रियाशील क्षेत्र	Training is an active area involving interaction, questioning, learning by doing, role plays, team games and practical activities.	परस्पर क्रियाएं पूछताछ करके सीखना, भूमिका अदा करना, सामूहिक खेल और प्रयोगात्मक क्रियाएं शामिल करते हुए प्रशिक्षण एक क्रियाशील क्षेत्र है।
29.	Middle Level Training Centres	मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र	This Ministry has prepared a Comprehensive Training Guidelines for selection of Middle Level Training Centres (MLTCs) and Anganwadi Workers' Training Centres (AWTCs) for selection of a suitable training institute.	उचित प्रशिक्षण संस्थान के चयन के लिए मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केंद्रों और आंगनवाडी कार्यकर्त्री प्रशिक्षण केंद्रों के चयन के लिए मंत्रालय ने व्यापक प्रशिक्षण दिशानिर्देश तैयार किए हैं।
30.	Digital India Programme	डिजिटल इंडिया कार्यक्रम	Under the Digital India Programme, this Ministry has launched e-Learning Web-portal www.nipccd-elearning.wcd.in on 25th May, 2016.	डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत इस मंत्रालय ने 25 मई, 2016 को ई-लर्निंग वेब पोर्टल www.nipccd-elearning.wcd.in शुरू किया है।
31.	Early Childhood Care and Education	प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा	Ministry has formulated the National Early Childhood Care and Education (ECCE) Policy and the scheme has been approved and notified by the Government of India in the gazette on 12.10.2013.	मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा (ईसीसीई) नीति निरूपित की है और भारत सरकार द्वारा इस नीति का अनुमोदन कर दिया है तथा 12.10.2013 के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया है।
32.	World Food Programme	विश्व खाद्य कार्यक्रम	WFP (World Food Programme) provides technical assistance to the Ministry at the central level and also provides technical support in Anganwadi Services Scheme implementation.	डब्ल्यूएफपी (विश्व खाद्य कार्यक्रम) : मंत्रालय को केंद्रीय स्तर पर तकनीकी सहायता और आईसीडीएस के कार्यान्वयन में भी तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है।
33.	Overall responsibility of monitoring the implementation	कार्यान्वयन की पूर्णरुपेण मॉनीटरिंग	The Ministry has the overall responsibility of monitoring the implementation of the Anganeadi Services Scheme.	आंगनवाड़ी सेवा स्कीम के कार्यान्वयन की पूर्णरुपेण मॉनीटरिंग करने का दायित्व मंत्रालय का है।
34.	For improving the nutritional status of women and	महिलाओं और बच्चों के पौषणिक स्तर में सुधार लाने	The objective of ICT-RTM is to get real time information on nutritional indicators for improving the nutritional status of women	आईसीटी-आरटीएम का उद्देश्य बुनियादी स्तर पर महिलाओं और बच्चों के पौषणिक स्तर में सुधार लाने के लिए

	children	के लिए	and children at grassroots level.	पौषणिक संसूचकों पर वास्तविक सूचना प्राप्त करना है ।
35.	Comprehensive scheme	व्यापक स्कीम	A comprehensive scheme for the holistic development of adolescent girls called Scheme of Adolescent Girls is being implemented in 205 selected districts across the country using te ICDS platform.	आईसीडीएस प्लेट फार्म का प्रयोग करके पूरे देश के 205 चुनिंदा जिलों में किशोरियों के समग्र विकास के लिए किशोरियों हेतु स्कीम नामक एक व्यापक स्कीम कार्यान्वित की जा रही है ।
36.	Non-nutrition component	गैर-पोषण घटक	The Government of India and States share the cost under non-nutrition component in ratio of 60:40.	भारत सरकार तथा राज्य 60:40 के अनुपात में गैर-पोषण घटक के तहत लागत वहन करते हैं ।
37.	Best practices	सर्वोत्तम प्रथाएं	The best practices and success stories have been shared by the States /UTs shile implementing the scheme.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों ने इस स्कीम के क्रियान्वयन में प्राप्त सफलता के किस्सों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया है।
38.	Home based skills	गृह आधारित कौशल	KSY is being implemented through the infrastructure of ICDS for addressing their needs of self-development, nutrition and health status, literacy and numerical skills, home based skills and life skill, etc.	किशोरी शक्ति योजना 11-18 आयु वर्ग की किशोरियों की स्व-विकास, पोषण और स्वास्थ्य स्तर, साक्षरता और अंकीय कौशल, गृह आधारित कौशल और जीवन कौशल आदि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आईसीडीएस अवसंरचना के माध्यम से चलाई जा रही है।
39.	Safety and well-being of children.	बच्चों की सुरक्षा एवं कल्याण	The Constitution of India places highest priority to the safety and well-being of children.	भारत का संविधान बच्चों की सुरक्षा एवं कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है ।
40.	Child abuse cases	बाल दुरूपयोग के मामले	To deal with child abuse cases, the Government has brought in a special law such as “The Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012”.	बाल दुरूपयोग के मामलों से निपटने के लिए सरकार द्वारा एक विशेष कानून अर्थात "यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम 2012" बनाया गया है ।
41.	Trainings and capacity building of functionaries	पदाधिकारियों के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण	NIPCCD is the nodal agency for trainings and capacity building of functionaries under the ICPS.	आईसीपीएस के तहत पदाधिकारियों के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के लिए निपसिड नोडल एजेंसी है ।
42.	National development Plan	राष्ट्रीय विकास योजना	The national development plans (Five Year Plans) of the Government of inida have aimed to ensure gender equality by addressing the concerns of men and women.	भारत सरकार की राष्ट्रीय विकास योजनाओं (पंचवर्षीय योजनाओं) का उद्देश्य पुरूषों और महिलाओं के सरोकारों को दूर करके लैंगिक समता का सुनिश्चय करना है।
43.	Gender Budgeting scheme	जेंडर बजटिंग योजना	Under the Gender Budgeting scheme, inter alia, the Ministry support to Central/State Government agencies on GB trainings and workshops.	जेंडर बजटिंग योजना के तहत मंत्रालय अन्य बातों के साथ जेंडर बजटिंग प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं पर केंद्रीय / राज्य सरकार की एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में लगा है।
44.	Statistics Bureau	सांख्यिकी ब्यूरो	The Statistics Bureau has represented the Ministry in various workshops in order to formulate the list of National indicators for the targets of SDG 5 and other gender and child related SDGs.	सांख्यिकी ब्यूरो ने एसडीजी-5 के लक्ष्यों तथा अन्य जेंडर एवं बच्चों से संबंधित सतत् विकास लक्ष्यों के लिए राष्ट्रीय संकेतकों की सूची तैयार करने हेतु विभिन्न कार्यशालाओं में मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया ।
45.	Sponsors the Projects	परियोजनाएं प्रायोजित करता है	The Ministry of Women & Child Development sponsors the projects on issues concerning to women and children for their welfare and development, including Food and Nutrition aspects .	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय खाद्य एवं पोषण के पहलुओं सहित महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण एवं विकास के क्षेत्रों में परियोजनाएं प्रायोजित करता है ।

46.	Grievance redressal mechanism	शिकायत निवारण तंत्र	The Grievance redressal mechanism is a part and parcel of an accountability machinery of any administration.	शिकायत निवारण तंत्र किसी प्रशासन की जवाबदेही तंत्र का एक भाग है
47.	Responsive and friendly to the people	लोगों के प्रति उत्तरदायी तथा उनके अनुकूल	To make the Ministry responsive and friendly to the people, an effective grievance redressal mechanism has been established in the Ministry.	मंत्रालय को लोगों के प्रति उत्तरदायी तथा उनके अनुकूल बनाने के लिए, मंत्रालय में कारगर शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की गई है ।
48.	Department of Administrative Reforms and Public Grievances	प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग	The Department of Administrative Reforms and Public Grievances (DARPG) has acknowledged this Ministry for redressing the public grievances in a very efficient manner.	प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने इस मंत्रालय द्वारा लोक शिकायतों को बहुत ही कुशल तरीके से निपटाया जाना स्वीकार किया है।
49.	Information Technology	सूचना प्रौद्योगिकी	The Ministry is using Information Technology extensively for implementation of e-Governance in several schemes and initiatives.	मंत्रालय कई योजनाओं और पहलों में ई-गवर्नेंस के कार्यान्वियन के लिए व्यापक रूप से सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है ।
50.	Online complaint Management System	ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली	She-Box is an online complaint Management System for lodging complaints related to sexual harassment at workplace.	कार्य-स्थल पर यौन उत्पीडन से संबंधित शिकायतें दर्ज कराने के लिए शी-बोक्स एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली है ।
51.	summarized	सारांश	NARI is an e-portal that summarizes over 350 government schemes for the benefit of women, with more being added every day.	नारी एक ई-पोर्टल है, जो महिलाओं के लाभ के लिए हर रोज और अधिक जोडे जाने के साथ 350 सरकारी योजनाओं का सारांश रखता है ।
52.	Authorized Media agencies.	प्राधिकृत मीडिया एजेंसियां	BBBP scheme is implemented through the office of Collectors/DMs/DCs in theDistricts and multi-media advocacy outreach through authorized media agencies.	बीबीबीपी योजना जिले में कलेक्टरों/डीएम/डीसी के कार्यालय के माध्यम से और प्राधिकृत मीडिया एजेंसियों के जरिए मल्टी-मीडिया आउटरीच के माध्यम से कार्यान्वित की गई है ।
53.	Child Adoption Resource Information & Guidance System	बाल दत्तकग्रहण संसाधन सूचना एवं मार्गदर्शी प्रणाली	Child Adoption Resource Information & Guidance System (CARINGS) is an e-governance initiative on adoption by Central Adoption Resource Authority for Smooth and transparent adoption process.	बाल दत्तकग्रहण संसाधन सूचना एवं मार्गदर्शी प्रणाली (केयरिंग) सुगम और पारदर्शी गोद लेने की प्रक्रिया के लिए केन्द्रीय दत्तक ग्रहण प्राधिकरण द्वारा गोद लेने पर एक ई-गवर्नेंस पहल है।
54.	Nutritional status	पोषण संबंधी स्थिति	The objective of ICT-RTM is to get real time information on nutritional indicators for improving the nutritional status of women and children at grass root level.	आईसीटी-आरटीएम का उद्देश्य जमीनी स्तर पर महिलाओं और बच्चों के पोषण संबंधी स्थिति में सुधार के लिए पोषण संबंधी संकेतकों पर वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करना है ।
55.	POCSO e-box	पॉक्सो ई-बॉक्स	POCSO e-box is available at http:// www.ncpcr.gov.in/user_compaints.	पॉक्सो ई-बॉक्स http://www. ncpcr.gov.in/user_ compaints- पर उपलब्ध है ।
56.	Empowering women and nurturing children	महिलाओं को सशक्त बनाना और बच्चों का संपोषित करना	The vision of the Ministry is empowering women and nurturing children.	मंत्रालय का दृष्टिकोण महिलाओं को सशक्त बनाना और बच्चों का संपोषित करना है।
57.	Food & Nutrition Board	खाद्य एवं पोषण बोर्ड	The Food & Nutrition Board (FNB), set up in 1964 under the Ministry of Food, was transferred to the Ministry of Women and Child Development in 1993 with all powers of a Central Government department.	खाद्य मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 1964 में गठित खाद्य एवं पोषण बोर्ड (एफएनबी) को वर्ष 1993 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में केंद्र सरकार के विभाग की सभी शक्तियों के साथ हस्तांतरित किया गया था।

58.	National Nutrition Mission	राष्ट्रीय पोषण मिशन	The Government is contemplating for setting up National Nutrition Mission (NNM) for looking of nutrition related issues in country.	सरकार, देश में पोषण से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने के लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन (एनएनएम) की स्थापना करने पर विचार कर रही है।
59.	Infant Milk Substitutes	शिशु दुग्ध अनुकल्प	FNB is also instrumental in acting as a powerful toll to protect, promote and support breastfeeding in the form of Infant Milk Substitutes, Feeding, Bottles and Infant Foods (Regulation of Production, Supply and Distribution), Act, 1992.	खाद्य एवं पोषण बोर्ड शिशु दुग्ध अनुकल्पण, पोषण बोत्ल और शिशु खाद्य (उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 1992 के रूप में स्तनपान के संरक्षण संवर्धन तथा सहायता के लिए एक सशक्त साधन के रूप में कार्य करने में भी सहायक है।
60.	Important indicator	महत्वपूर्ण संकेतक	The Nutritional status of the country has been recognized as an important indicator of national development.	देश की पोषण स्थिति को राष्ट्रीय विकास के एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में स्वीकार किया गया है।
61.	Nutrition and Health components	पोषण एवं स्वास्थ्य घटक	Anganwadis under different ICDS projects are being visited to monitor the supplementary nutrition and to facilitate the nutrition and health components of the ICDS.	विभिन्न आईसीडीएस परियोजनाओं के अधीन आंगनवाडियों का पूरक पोषण की मानिटरिंग तथा आईसीडीएस के पोषण एवं स्वास्थ्य घटकों को सुकर बनाने के लिए दौरा किया जाता है।
62.	Safe and Hygienic food	सुरक्षित तथा स्वास्थ्यकर भोजन	Providing safe and hygienic food meeting the nutrition and health norms is as essential as providing food to these beneficiaries.	लाभार्थियों को सुरक्षित तथा स्वास्थ्यकर भोजन उपलब्ध कराना, जो पोषण एवं स्वास्थ्य के मानदंडो को पूरा करता हो, उतना ही आवश्यक है जैसे कि उन्हें भोजन उपलब्ध कराना है।
63.	Active cooperation	सक्रिय सहयोग	Various events on specific themes were organized with the active cooperation of respective State Governments, Education Institutions, NGOs and Media.	संबंधित राज्य सरकारों, शैक्षणिक संस्थानों गैर-सरकारी संगठनों तथा मीडिया सक्रिय सहयोग से विशिष्ट विषयों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।
64.	National Nutrition Week	राष्ट्रीय पोषण सप्ताह	National Nutrition Week (NNW) is celebrated from 1st -7th September every year since 1982 to intensify nutrition awareness through various modes and interventions to reach the masses in the far flung areas of the country.	राष्ट्रीय पोषण सप्ताह (एनएनडब्ल्यू) प्रत्येक वर्ष 1.7 सितंबर तक देश के दूर-दराज क्षेत्रों में जनसमूह तक पहुंचने के लिए विभिन्न तरीकों तथा अर्न्तक्षेपों के माध्यम से पोषण जागरूकता में गति लाने के लिए मानया जाता है।
65.	Nutritional status of the community	समाज की पौषणिक स्थिति	The nutritional status of the community is recognized as an important indicator of national development.	समाज की पौषणिक स्थिति राष्ट्र के विकास के महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में स्वीकार की गई है।
66.	Coordination Division	समन्वय प्रभाग	Coordination Division is instrumental in compiling, collaborating and coordinating various activities of the Board and providing key information & feedback to MWCD.	समन्वय प्रभाग बोर्ड के विभिन्न क्रियाकलापों को संकलित करने, सहयोजित करने और समन्वय करने तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को महत्वपूर्ण सूचना तथा फीडबैक उललब्ध कराने में सहायता प्रदान करता है।
67.	Safeguard and promote the rights and interests of women	महिलाओं के अधिकारों एवं हितो की रक्षा करने एवं बढावा देना	In pursuance of the National Commission for Women Act, 1990, the National Commission for Women (NCE) was constituted on 31st January, 1992 as a statutory body to safeguard and promote the rights and interests of women.	राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अनुसरण में महिलाओं के अधिकारों एवं हितो की रक्षा करने एवं बढावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर

				सांविधिक निकाय के रूप में 31 जनवरी, 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) का गठन किया गया था।
68.	Mandate	अधिदेश	The Commission, in pursuance of its mandate, has been taking steps to progressively increase awareness about the laws, rights and entitlements of women in the society as a whole.	राष्ट्रीय महिला आयोग अपने अधिदेश के अनुसरण में समग्र रूप से समाज में महिलाओं के कानूनों अधिकारों और अधिकारिता के बारे में क्रमिक रूप से जागरूकता बढाने के उपाय करता रहा है।
69.	Right of Free and Compulsory Education	नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार	NCPCR has been mandated to monitor 'Right of Children to Education' under the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009.	एनसीपीसीआर को बाल नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009 के अंतर्गत बाल शिक्षा अधिकार की निगरानी का आदेश दिया गया है।
70.	Transparency	पारदर्शिता	To ensure best interest of children; citizen centric approach enabling Prospective Adoptive Parents (PAPs) to take informed decision; online registration, referral (based on seniority), reservation & matching system and eliminating offline matching for transparency.	बच्चों के सर्वोत्तम हित सुनिश्चित करने के लिए सूचित निर्णय लेने, ऑनलाइन पंजीकरण, रैफरल (वरिष्ठता पर आधारित), आरक्षण एवं मिलन प्रणली और पारदर्शिता के लिए ऑफ्लाइन मैचिंग को खत्म करने में भावी दत्तक-ग्रहण योग्य माता-पिता (पीएपी) को अधिकार देने के लिए नागरिक केंद्रिक दृष्टिकोण अपनाना।
71.	Official website	अधिकारिक वेबसाइट	Child Adoption Resource Information & Guidance System (CARINGS), an e-governance initiative on adoption, was launched in February 2001 and hosted in the official website of CARA i.e. www.cara.nic.in.	बाल दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना एवं मार्गदर्शन प्रणाली दत्तक-ग्रहण पर ई-गवर्नेस की पहल है जो फरवरी, 2011 को शुरू हुई थी और कारा की आधिकारिक वेबसाइट यानि www.cara.nic.in पर अपलोड है।
72.	Hard to place children	दुष्करणीय नियोजन योग्य बच्चे	CARINGS has facilitated adoption of hard to place children through a newly introduced immediate placement module.	बाल दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना एवं मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स) ने नए प्रारंभ किए तत्काल नियोजन मॉडयूल्स के माध्यम से दुष्करणीय नियोजन योग्य बच्चों के दत्तक-ग्रहण को आसान बनाया है।
73.	Prospective Adoptive Parents	भावी दत्तक-ग्रहण योग्य माता-पिता	The Adoption Regulations have been framed keeping in mind the issues and challenges faced by CARA and other stake holders including the Adoption Agencies & Prospective Adoptive Parents (PAPs).	दत्तकग्रहण एजेंसियों एवं भावी दत्तक-ग्रहण योग्य माता-पिता (पीएपी) सहित केंद्री य दत्तग्र-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) और अन्य संबंधित हितधारकों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाईयों एवं चुनौतियों को ध्यान में रखकर दत्तक-ग्रहण विनियम तैयार किए गए हैं।
74.	Table of the House	सदन के पटल	Statement is laid in the Table of the House	विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।
75.	Commission for Protection of Child Rights	बाल अधिकार संरक्षण आयोग	The NCPCR, under Section 13 of "The Commissions for Protection of Child Rights (CPCR) Act, 2005 is mandated to enquire into complaints related to the violation of child rights.	एनसीपीसीआर के लिए, बाल अधिकार संरक्षण आयोग (सीपीसीआर) अधिनियम, 2005 की धारा 13 के अंतर्गत बाल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करना अनिवार्य है।
76.	Cases of sexual offences	यौन अपराधों के मामलों	The POCSO e-box launched by the Commission to deal with the cases of sexual offences against children under POCSO Act, 2012 remained in practice.	पोक्सो अधिनियम, 2012 के अंतर्गत बच्चों के विरूद्ध यौन अपराधों के मामलों को निपटाने के लिए आयोग द्वारा शुरू किया गया पोक्सो ई-बॉक्स विद्यमान रहा।

77.	Budgetary Support	बजटीय सहायता	The budgetary support received from the Government is in the form of Corpus Fund which is utilized for lending purposes by RMK.	सरकार से प्राप्त बजटीय सहायता (कार्पस) निधि के लिए है। राष्ट्रीय महिला कोष इसका उपयोग ऋण देने के लिए करता है।
78.	Joint Liability Groups	संयुक्त देयता समूह	Rashtriya Mahila Kosh provides micro-credit to women Self-Help Groups (SHGs) /Joint Liability Groups (JLGs) including women micro-entrepreneurs in both rural and urban areas.	राष्ट्रीय महिला कोष ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में महिला सूक्ष्म-उद्यमियों सहित महिला स्वयं सहायता समूहों एवं संयुक्त देयता समूहों (जे.एल.सी) को अल्प ऋण प्रदान करता है ।
79.	Micro-credit	अल्प ऋण	RMK extends micro-credit to women in the informal sector for livelihood activities micro-enterprises. Housing ect.	राष्ट्रीय महिला कोष अनौपचारिक क्षेत्र में गरीब महिलाओं को आय सृजन गतिविधियों, सूक्ष्म उद्यम, मकान बनाने, के लिए अल्प ऋण प्रदान करता है।
80.	Capacity building	क्षमता निर्माण	The Ministry of women and child development constituted an Outreach Committee for expanding the network of RMK and Mahila E-haat along with their capacity building.	आरएमके और महिला ई-हाट के नेटवर्क को बढाने और उनकी क्षमता निर्माण के लिए डॉ. नंदिनी आज़ाद की अध्यक्षता में 21/12/2017 को आउटरीच समिति का गठन किया गया है ।
81.	Management committee	प्रबंध समिति	RMK through mail, invited NGOs with women as their Chief Functionary or having majority women in their management committee, registered with NGO Darpan Portal of NITI Aayog to avail the benefit of RMK loan schemes.	आरएमके ने मेल द्वारा उन एनजीओज़, जिनकी मुख्य पदाधिकारी महिलाएं हैं अथवा जिनकी प्रबंध समिति में महिलाएं बहुमत में हैं, को आरएमके ऋण योजनाओं का लाभ उठाने के लिए नीति आयोग के एनजीओ पोर्टल पर पंजीकृत कराने के लिए आमंत्रित किया है।
82.	Vigilance Awareness Week	सतर्कता जागरूकता सप्ताह	The Vigilance Awareness Week was observed from 30th October, 2017 to 4th November 2017 on the theme “My Vision Corruption Free India” “Mera Lakshya – Bhrastachar Mukt Bharat”.	30 अक्टूबर, 2017 से 4 नवंबर, 2017 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया । इस वर्ष इस सप्ताह का विषय-सार था । "मेरा लक्ष्य-भ्रष्टाचार मुक्त भारत"।
83.	Employees and Consultants	कर्मचारी और सलाहकार	“Rashtriya Ekta Diwas (National Unity Day)”was observed in Rashtriya Mahila Kosh on 31st October 2017. The Employees and Consultants of RMK took pledge and reiterated their firm commitment to the cause of National Unity.	राष्ट्रीय महिला कोष में 31 अक्टूबर, 2017 को "राष्ट्रीय एकता दिवस" मनाया गया इस अवसर पर आरएमके के कर्मचारियों और सलाहकारों ने प्रतिज्ञा की और राष्ट्रीय एकता के लिए अपनी दृढ प्रतिबद्धता दोहराई ।
84.	Promote the activity of thrift and credit a	बचत और ऋण गतिविधियों में प्रोत्साहित करना	RMK provides small loans maximum up to Rs. 10 lakh, to promote the activity of thrift and credit among new and smaller but potentially capable organizations having at-least six months experience in information of SHGs, thrift, credit and recovery management.	राष्ट्रीय महिहला कोष नए और छोटे सक्षम संगठनों को बचत और ऋण गतिविधियों में प्रोत्साहित करने के लिए अधिकतम रूपये 10 लाख तक के छोटे ऋण देता है ।
85.	Marketing platform	विपणन प्लेटफॉर्म	This online marketing platform facilitates direct contact between the vendor and buyer personal contact, telephone and e-mail.	ऑनलाइन विपणन प्लेटफॉर्म विक्रेता और क्रेता के बीच सीधे संपर्क-निजी सम्पर्क, टेलीफोन नंबर, ई-मेल की सुविधा प्रदान करता है।
86.	Showcase the products	उत्पादों को प्रदर्शित करना	Efforts are made to reach out and bring different women from across the country to showcase their products / services on	महिला ई-हाट पोर्टल का हिस्सा बनने और अपने उत्पादों/सेवाओं को इस पोर्टल

			Mahila E-haat portal.	पर प्रदर्शित करने के लिए देश भर के विभिन्न महिला समूहों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है।
87.	Income generation activities	आमदनी पैदा करने की गतिविधियां	RMK fund is given to women beneficiaries for income generation activities across sectors as mentioned below.	राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा महिला लाभार्थियों को निम्नलिखित क्षेत्रों में अपनी आमदनी पैदा करने के लिए ऋण प्रदान किया जाता है ।
88.	Medical expenses	चिकित्सा व्यय	Consumption loan for purposes such as medical expenses, marriage, etc. shall not be more than 1 % of total amount given by IMOs to women beneficiaries.	आईएमओज़ द्वारा महिला लाभार्थियों को दिए जाने वाले ऋण के 1% से अधिक चिकित्सा व्यय, विवाह आदि जैसे उद्देश्यों के लिए उपयोग ऋण नहीं दिया जायेगा ।
89.	Police and Public Order	पुलिस और कानून व्यवस्था	Police and Public Order are state subjects	पुलिस और कानून व्यवस्था राज्य के विषय हैं ।
90.	Positive change	सकारात्मक परिवर्तन	Government recognizes that the incidence of crime against women and children cannot be controlled unless mindset of people, in general, undergoes a positive change.	सरकार का यह मानना है कि महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध अपराध की घटना तब तक नियंत्रित नहीं हो सकती जब तक कि सामान्यतया लोगों की सोच में सकारात्मक परिवर्तन नहीं आएगा ।
91.	Criminal Procedure Code.	दंड प्रक्रिया संहिता	As per provisions of Section 357A of CrPC, States/UTs must notify the victim compensation Scheme.	दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357ए के प्रावधानों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पीडित मुआवजा स्कीम अधिसूचित करनी चाहिए।
92.	Priorities and perspective.	प्राथमिकाताओं और परिप्रेक्ष्य	Ensure that the work of the Commission is directly informed by the views of children in order to reflect priorities and perspective.	यह सुनिश्चित करना कि प्राथमिकाताओं और परिप्रेक्ष्य को परावर्तित करने के उद्देश्य से आयोग का कार्य प्रत्यक्ष रूप से बालकों के विचारों से प्रेरित हैं;
93.	Promote the views of children	बच्चों के विचारों का संवर्धन करना	Promote, respect and serious consideration of the views of children in its work and in that of all Government Departments and Organizations dealing with child.	बालकों से संबंधित सभी सरकारी विभागों और संगठनों के कार्य में बालकों के विचारों का संवर्धन करना, उन्हें सम्मान देना और उन पर गंभीरतापूर्वक विचार करना
94.	Undertake formal investigations	औपचारिक अन्वेषण करना	Undertake formal investigations where concern has been expressed either by children themselves or by concerned person on their behalf.	जहां स्वयं बच्चों द्वारा या उनकी ओर से संबंधित व्यक्ति द्वारा सरोकार उठाए गए हैं, वहां औपचारिक अन्वेषण करना,
95.	Effective implementation	प्रभावी क्रियान्वयन	Examine and review the safeguards for rights provided by or under this Act and Recommend measures for their effective implementation.	इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उपबंधित अधिकारों के संरक्षण के लिए रक्षोपायों की परीक्षा और पुनर्विलोकन करना तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना ।
96.	Inquire into complaints	शिकायतों की परीक्षा करना	Inquire into complaints relating to child's right to free and compulsory education.	बालकों का नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार से संबंधित शिकायतों की परीक्षा करना।
97.	Commissions for Protection of Child Rights	बालक अधिकार संरक्षण आयोग	Take necessary steps as provided under sections 15 and 24 of the said Commissions for Protection of Child Rights Act.	उक्त बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम की धारा 15 और 24 के उपबंधों के अनुसार आवश्यक उपाय करना ।
98.	violations of child rights	बाल अधिकारों के अतिक्रमण	Inquire into violation of child rights and recommend initiation of proceedings in such cases.	बाल अधिकारों के अतिक्रमण की जांच करना और ऐसे मामलों में कार्यवाहीयां आरंभ करने की सिफारिश करना,
99.	Incorporation of child rights	बालक अधिकारों के समावेशन	Promote the incorporation of child rights into the school curriculum, teachers training and training of personnel dealing with	स्कूली पाठयक्रम, अध्यापकों के प्रशिक्षण तथा बालकों से संबंधित कार्मिकों के

			children.	प्रशिक्षण में बालक अधिकारों के समावेशन को बढावा देना।
100.	Monitor in the implementation	क्रियान्वयन की निगरानी करना	To monitor in the implementation of Protection of children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012.	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 के क्रियान्वयन की निगरानी करना।